Diary no. 14/18/452

To Repair the Bridges

32 Sh. AMIT SIHAG (Dabwali):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) the steps taken by the Government in co-ordination with Rajasthan Government for the urgent repair/reconstruction of bridges on Indira Gandhi Canal and Sirhind feeders in Dabwali Assembly Constituency which are in damaged condition and due to that its lay to loss of life and property; and

b) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following bridges:-

i) on mandi Dabwali to Sangria road (Crossing Indira Gandhi Canal) ;

ii) on village Ganga to Abubshahar road (Crossing Indira Gandhi Canal);

iii) on village Ganga to Chautala road (Crossing Indira Gandhi Canal) ;

iv) on village Sakta khera to Lohgarh road (Crossing Sirhind link channel); and

v) on village Sakta khera to Lohgarh road (Crossing Sirhind feeder) ?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana.

a) Indira Gandhi Feeder (I.G.F) off-takes from Harike Barrage in Punjab State and it passes through state of Haryana from RD 491000 to 555000 and then enters in Rajasthan State. Its repair and maintenance work is being carried out by the Punjab Irrigation authorities in the Jurisdiction of Punjab and Haryana State. It is important to mention here that the work of cement concrete lining from RD 496000 to 555000 of I.G.F. has been completed by Rajasthan Irrigation Department. The bridges in the territory of Haryana State on Indira Gandhi Canal Feeder and Sirhind Feeder are in dilapidated condition being about 60 years old. There is tress passing of heavy vehicle such as Combine, Buses, Tractor-Trolly, Heavy-Trolla etc. through these bridges. The water of I.G.F. is meant for Rajasthan State, whereas watch and ward and maintenance is being done by Punjab authority. Therefore, Irrigation & Water Resources Department, Haryana cannot execute the work in this regard. Many correspondences regarding repair/reconstruction of these bridges have been made from time to time with Punjab authorities as well as Rajasthan authorities, but without any outcome/response from them so

far. Haryana Govt. will take up this proposal on priority at highest level with Punjab Govt.

b) There is no proposal under consideration of the Govt. to repair the said bridges.

Diary no. 14/18/452

पुलों की मरम्मत करना

32 श्री अमित सिहाग (डबवाली):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) डबवाली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर तथा सरहिंद फीडरों पर बांधों की तत्काल मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के समन्वय से सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए, जिनकी क्षतिग्रस्त अवस्था होने के कारण जान–माल का नुकसान हो रहा है; तथा

ख) क्या निम्नलिखित पुल की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैः–

(i) मंडी डबवाली से संगरिया सड़क पर (क्रॉसिंग इंदिरा गांधी नहर);

(ii) गांव गंगा से अबूबशहर सड़क पर (क्रॉसिंग इंदिरा गांधी नहर);

(iii) गांव गंगा से चौटाला सड़क पर (क्रॉसिंग इंदिरा गांधी नहर);

(iv) गांव सकता खेड़ा से लोहगढ़ सड़क पर (क्रॉसिंग सरहिंद लिंक चैनल); तथा

(v) गांव सकता खेड़ा से लोहगढ़ सड़क पर (क्रॉसिंग सरहिंद फीडर)?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

(क) इंदिरा गांधी फीडर (आई.जी.एफ) पंजाब राज्य में हरिके बैराज से निकलती है और यह हरियाणा राज्य में बुर्जी संख्या 491000–555000 से होकर गुजरती है और फिर राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसकी मरम्मत और रखरखाव का कार्य पंजाब और हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में पंजाब सिंचाई प्राधिकरणों द्वारा किया जाता रहा है। यहां यह बताना जरूरी है कि राजस्थान सिंचाई विभाग द्वारा इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी संख्या 496000 से 555000 तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। हरियाणा राज्य के क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर पर बने पुल लगभग 60 वर्ष पुराने होने के कारण जीर्ण–झीर्ण हालत में हैं। इन पुलों से भारी वाहन जैसे कंबाइन, बसें, ट्रैक्टर–ट्रॉली, हैवी–ट्रॉला आदि का आवगमन होता है। इंदिरा गांधी फीडर का पानी राजस्थान राज्य के लिए है, जबकि निगरानी और रख–रखाव पंजाब प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इन पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के संबंध में समय–समय पर पंजाब

प्राधिकरणों के साथ–साथ राजस्थान प्राधिकरणों के साथ कई पत्राचार किए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई परिणाम/प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हरियाणा सरकार इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर पंजाब सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाएगी।

ख) उक्त पुलों की मरम्मत के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।